

मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण

प्रलिस के लयः

[महातमा गांधी राषट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#), [सामाजिक अंकेक्षण](#), [अमृत सरोवर](#), [जलदूत एप](#)

मेन्स के लयः

मनरेगा के कार्यानवयन के मुद्दे, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप, वकिस से संबंघति मुद्दे

[स्रोत: द हद्वि](#)

चरचा में क्यौं?

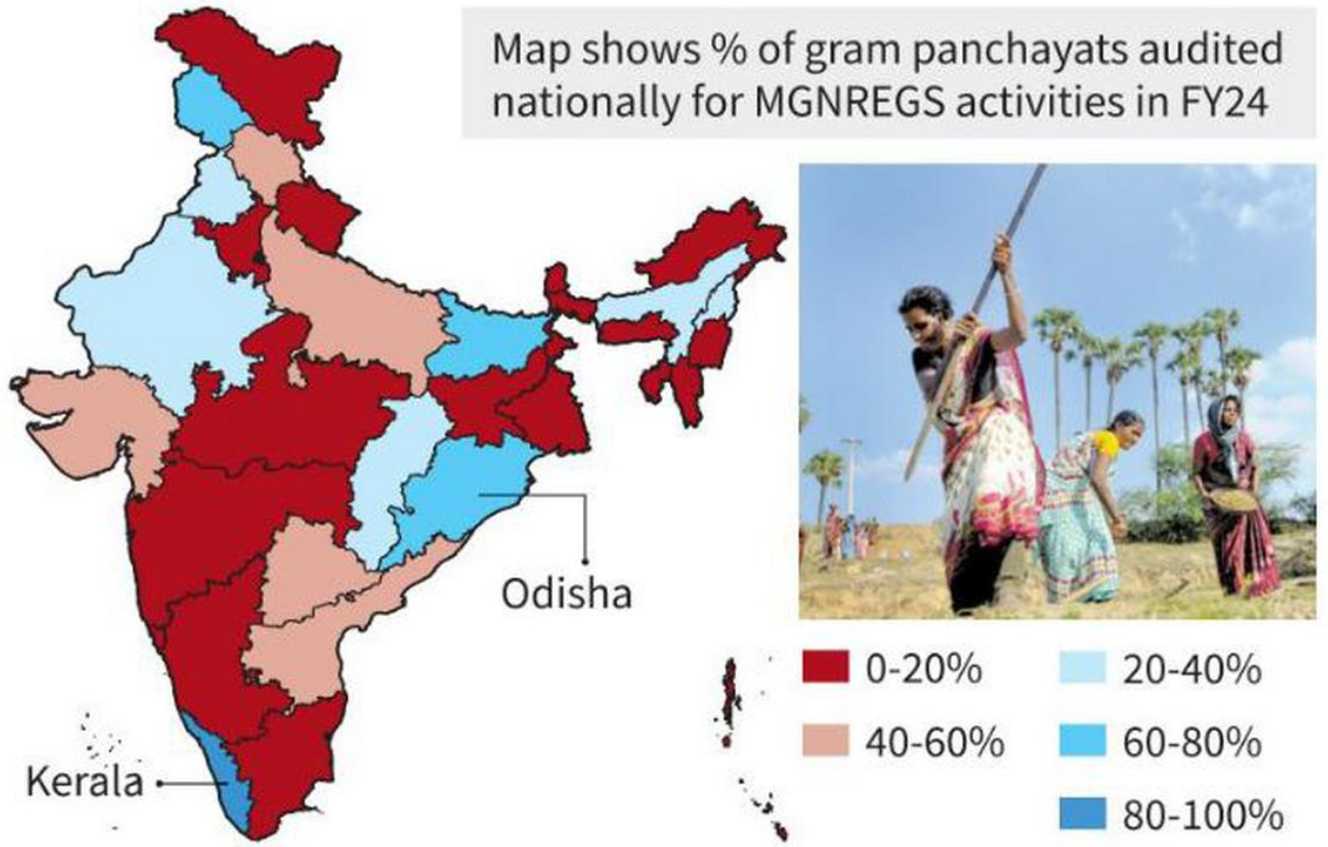
ग्रामीण वकिस मंत्रालय (MoRD) द्वारा अनुरकषति [सामाजिक अंकेक्षण](#) पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) का हालया डेटा [महातमा गांधी राषट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#) में सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति और चुनौतयिँ पर प्रकाश डालता है।

मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति क्या है?

- सामाजिक अंकेक्षण पर MIS के आँकड़ों के अनुसार, 34 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में से केवल **6** ने ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कयि गए कार्यों के **सामाजिक अंकेक्षण को पूरा करने में 50% का आँकड़ा** पार कर लया है।
- सामाजिक अंकेक्षण में व्यापक और समावेशी दृषटकिण का प्रदर्शन करते हुए ग्राम पंचायतों में 100% कवरेज** हासलि कर केरल अग्रणी बनकर उभरा है।
 - केरल के अलावा पाँच अन्य राज्यों ने सामाजिक अंकेक्षण कवरेज में 50 प्रतिशत का आँकड़ा पार कर लया है, जनिमें **बिहार (64.4 %)**, **गुजरात (58.8 %)**, **जम्मू-कश्मीर (64.1 %)**, **ओडिशा (60.42 %)** और **उत्तर प्रदेश (54.97 %)** शामिल हैं।
- केवल तीन राज्यों तेलंगाना (40.5%), हिमाचल प्रदेश (45.32%) और आंध्र प्रदेश (49.7%) ने 40% या अधिक गाँवों को कवर कया है।
- तेलंगाना के अलावा चुनाव वाले राज्यों में संख्या वास्तव में कम है जनिमें मध्य प्रदेश (1.73%), मज़ोरम (17.5%), छत्तीसगढ़ (25.06%) और राजस्थान (34.74%) हैं।

Audited panchayats

Kerala is the only State that has completed social audits of all activities done under MGNREGS in each of its Gram Sabhas



Source: Union Ministry of Rural Development (as of November 10, 2023)

//

सामाजिक अंकेक्षण क्या है?

परिचय:

- सामाजिक अंकेक्षण **आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने** और यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि क्या राज्य द्वारा रिपोर्ट किये गए व्यय ज़मीन पर खर्च किये गए वास्तविक धन को दर्शाते हैं।
- सामाजिक अंकेक्षण **मनरेगा अधिनियम, 2005 में अंतरनिहित भ्रष्टाचार वसिधी तंत्र** है।
 - इसमें मनरेगा के तहत बनाए गए बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता, मज़दूरी में वित्तीय हेराफेरी और किसी भी प्रक्रियात्मक वचिलन की जाँच करना शामिल है।

उद्देश्य:

- स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सामाजिक अंकेक्षण नागरिकों को सरकारी पहलों की दक्षता और प्रभावशीलता की जाँच तथा मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है।

वैधानिक फ्रेमवर्क:

- मनरेगा के संदर्भ में **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)** की धारा 17 ग्राम सभा को कार्यों के

नषिपादन की नगिरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिये कानूनी आधार प्रदान करने का आदेश देती है।

- **योजना नयिम अंकेक्षण, 2011**, जसि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की लेखापरीक्षा नयिम, 2011 के रूप में भी जाना जाता है, **भारत के नयितरक और महालेखा परीक्षक (CAG)** के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसिति कयि गए थे।
 - ये नयिम देश भर में पालन कयि जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण की प्रकरयिओं और **सोशल ऑडिट यूनिट (SAU)**, राज्य सरकार एवं मनरेगा के फीलड कार्यकर्ताओं सहति वभिनिन संस्थाओं के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
 - सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों **कार्यान्वयन प्राधिकारयिों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती** हैं, जसिसे कार्यक्रमों का नषिपक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित होता है।
 - सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लयि वे गत वर्ष राज्य द्वारा कयि गए **मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर धनराशि** के हकदार हैं।
 - ऐसे मामलों में जहाँ राज्य नयिमति सामाजिक अंकेक्षण करने में वफिल रहते हैं, केंद्र के पास मनरेगा के तहत आवंटति धन के वतिरण को रोकने का अधिकार है।
- **कार्यान्वयन में चुनौतयिों:**
 - सामाजिक अंकेक्षण के लयि वैधानिक फ्रेमवर्क विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के बीच सीमति जागरूकता के चलते इस प्रकरयि में उनकी सकरयि भागीदारी को बाधति कर सकता है।
 - सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों के लयि सीमति वतितीय संसाधन उनकी गतिविधयिों के दायरे को सीमति करते हुए संपूर्ण और प्रभावी ऑडिट करने की उनकी क्षमता से समझौता कर सकते हैं।
 - **राजनीतिक प्रभाव** सामाजिक अंकेक्षण की नषिपक्षता में बाधा डाल सकता है, जसिसे मूल्यांकन प्रकरयि की प्रामाणिकता व नषिपक्षता प्रभावति हो सकती है।
 - **कार्यान्वयन प्राधिकारयिों एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के सहयोग और समन्वय का अभाव**।
 - सामाजिक अंकेक्षण रपिर्टों के नषिकर्षों और सफारिशों पर अनुवर्ती नरितरता एवं कार्रवाई का अभाव।
 - नहिति स्वार्थों की वजह से धमकयिों और उत्पीड़न का सामना करने वाले सामाजिक लेखा परीक्षकों और **मुखबरिों के लयि सुरक्षा** और समर्थन का अभाव।

मनरेगा:

परचय:

- MGNREGS वर्ष 2005 में **ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा शुरू कयि गए विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
 - मनरेगा एक वैधानिक फ्रेमवर्क है जो योजना के कार्यान्वयन को सकषम बनाता है और **ग्रामीण गरीबों को काम करने का अधिकार** देती है।
- MGNREGS के तहत कुल 11.37 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त कयि और (15 दसिंबर, 2022 तक) कुल 289.24 करोड़ व्यक्त-दविस रोजगार उत्पन्न हुआ है।

उद्देश्य:

- यह योजना प्रत्येक वतितीय वर्ष में कसि भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को **100 दिन के रोजगार की गारंटी देती** है जो सार्वजनिक कार्य-संबंधति अकुशल मजदूरी करने के लयि तैयार हैं।
- गरीबों के **आजीविका संसाधन** आधार को मजबूत करना।
- सकरयि रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।
- **पंचायती राज संस्थाओं (PRI)** को सशक्त बनाना।

मनरेगा की उपलब्धयिों

- मंत्रालय ने **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** का उपयोग करके **वाटरशेड विकास सदिधांतों** (रजि टू वैली एप्रोच) के आधार पर ग्राम पंचायतों की एक एकीकृत समग्र योजना शुरू की है।
 - इसे दसिंबर 2022 तक 2,62,654 ग्राम पंचायतों की योजनाओं को तीन वर्ष में पूरा करने के लक्ष्य के साथ डजिाइन कयि गया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नधि प्रबंधन प्रणाली (NeFMS)/डीबीटी:

- मनरेगा के तहत 99% मजदूरों को उनकी मजदूरी सीधे उनके बैंक/डाकघर खातों में प्राप्त हो रही है।
- यह पारदर्शति तथा समय पर वेतन जारी करने की दशिा में एक बड़ा कदम है।

सेक्योर (SECURE):

- SECURE एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जसि विशेष रूप से मनरेगा कार्यो के लयि अनुमान तैयार करने तथा अनुमोदन हेतु डजिाइन एवं विकसिति कयि गया है।

कौशल विकास:

- परयोजना "उन्नति" का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों के कौशल-आधार को उन्नत करना और इस तरह उनकी आजीविका में सुधार करना है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें।
 - दसिंबर 2022 तक 27,383 उम्मीदवारों को प्रशिक्षति कयि जा चुका है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लयि नई पहलें:

- **अमृत सरोवर**
- **जलदत्त एप**
- **लोकपाल**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नम्निलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम" से लाभान्वति होने के पात्र हैं? (2011)

- (a) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य
- (b) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (c) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य
- (d) किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/social-audits-in-mgnregs>

